Inclusion of staff artists of AIR and Doordarshan in IBPS

1683. DR. NARREDDY THULASI REDDY : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

' (a) whether the staff artists, recently, declared as civil servants of AIR and Doordarshan are included in Indian Broadcasting 'Programme Service ;

(b) if so, the details thereof; and (e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO) : (a) to (c) The erstwhile staff artists of AIR and Doordarshan drawing the fee scale equivalent to that of Group 'A' civil post, since declared as Government servants, whose nature of duties were akin to those of the regular programme staff were inducted into IBCP)S.

अयोध्या में पत्रकारों पर हुए हमले के संबंध में प्रेस परिषद् की रिपोर्ट

1684. **डा० बापू कालदाते :**

श्री चतुरानन मिश्र :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रेस परिषद् ने 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में पत्रकारों पर हुए हमले के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार भविष्य में पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान किए जाने पर विचार कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) पत्रकारों को यातनाएं दिये जाने के सम्बन्ध में भारतीय प्रेस परिषद् को जनवरी, 1992 से फरवरी, 1993 की अवधि के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(च) प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) प्रेस परिषद् की रिपोर्ट में परिषद् द्वारा निकाले गए निष्कर्ष तथा सिफारिशें शामिल हैं। इन सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ मीडिया व्यक्तियों पर प्रहार करने वाले दोषी व्यक्तियों से स्पष्टीकरण मांगना; प्रतिपूर्ति की व्यवस्था के लिए सामाजिक बीमा जैसी मद पर सरकार द्वारा विचार करना; समाचार-पत्र संगठनों द्वारा विशेष जोखिम बीमा पालिसी के मुद्दे को उठाना; पत्रकारों द्वारा स्वयं बढ़ते हुए खतरों पर काबू पाने के लिए उपाय सुझाना, सरकार द्वारा उपस्कर के आयात और क्षतिग्रस्त/गुम हुई आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क के भुगतान को हटाया जाना शामिल हैं।

(ग) और (घ) पत्रकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। तथापि केन्द्र सरकार ने पत्रकारों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समय-समय पर विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किए हैं।

(ङ) और (च) अड़तालीस शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से पच्चीस प्रारम्भ में ही अभियोजन की कमी/जांच पड़ताल के लिए पर्याप्त आधार के न होने/मामला न्यायाधीन होने/प्रेस परिषद् के कार्य क्षेत्र से बाहर होने/मामले को वापस ले लेने के कारण खारिज कर दिए गए थे। शेष तेईस शिकायतें जांच के विभिन्न चरणों में हैं।